पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके वैश्विक चेतना को अपने पक्ष में किया है और हर कदम पर पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर किया है. इसी दबाव के चलते पाकिस्तान को हमारे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है. लगातार अलग-थलग पड़ते पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र में भी मुंह की खानी है...

पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुआ वैश्विक समुदाय

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

डॉ जे जगन्नाथन
दक्षिण एशिया व न्यूक्लियर मामलों के जानकार

सरकार की बदौलत वैश्विक चेतना हमारे पक्ष में

हमारे कूटनीतिज्ञों और विदेश मंत्री ने केवल 2-3 दिनों के भीतर ही वैश्विक समर्थन जुटाया और पाकिस्तान पर अभिनंदन को छोड़ने का ऐसा दबाव कायम किया, जिससे पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना पड़ा. वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान ने अपनी छवि बना ली है कि वह दुनियाभर के देशों से मदद मांगता फिरता है, जबकि दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर करता है और आतंकियों को पनाह देता है.

विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी भारत की बहुत महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक (कूटनीतिक) जीत है. ऐसे समय में, जब युद्ध जैसी स्थिति के बीच चारों तरफ युद्धोन्माद के बादल के छाये हुए हैं, केंद्र सरकार ने शांति बनाये रखते हुए, देश के नागरिकों को बिना परेशान किये, सभी को युद्ध की मानसिक यंत्रणा से बचाते हुए स्थिति को संभाला है. सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है. उदाहरण के लिए, याद कीजिए साल 2001 का समय, संसद पर हमला हुआ था और देश में संकट की स्थिति पैदा हुई थी, युद्ध की आशंका भी थी, देश में एक डर का माहौल था. ऐसे कई मौके अतीत में भारत के सामने आये हैं. लेकिन, पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सरकार ने टीम-वर्क के साथ बहुत आराम व शांति से स्थिति को संभाल लिया है और देश पर कोई आंच नहीं आने दी है.

कूटनीतिक दृष्टि से बात करें, तो हमारी ऊर्जस्वी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के लिए वुहान (चीन) गयी और भारत की एयर स्ट्राइक का विस्तृत पक्ष उनके सामने रखा. विदेश मंत्री ने पुलवामा हमले से लेकर पाकिस्तान के आतंकी व्यवहार और एयर स्ट्राइक की जरूरत का महत्व उन्हें समझाया और रूस व चीन को भारत के पाले में किया. इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर पुलवामा हमले और आतंकवाद के मसले पर भारत के पक्ष में देश खड़े हुए हैं. इसी क्रम में भारत के कूटनीतिज्ञों ने चीन पर असर डाला, जिससे चीन भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं दिखा. चीन के वुहान शहर में हुई बैठक

को रद्द करने की मांग पाकिस्तान ने चीन से की थी, लेकिन चीन नहीं माना. इसलिए, पाकिस्तान चीन से खफा भी चल रहा है. इससे, पाकिस्तान और चीन के घरेलू संबंधों/योजनाओं पर भी असर पड़ा है. इस बात से यह भी स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं चलता रहेगा कि पाकिस्तान कुछ भी करता रहेगा और चीन उसकी मदद करता रहे.

रूस के साथ संबंधों ने हमारी बहुत मदद की है. अमेरिका भी हमारे पक्ष में खड़ा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने एयर स्ट्राइक के पहले ही कह दिया था कि कुछ गंभीर होनेवाला है. इसका साफ मतलब है कि उन्हें भी पता था कि भारत क्या करनेवाला है और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के हमारे जरूरी कदम के वे पक्ष में थे. पाकिस्तान केवल इन्हीं देशों के बीच अलग-थलग नहीं पड़ गया है. अबु धाबी में चल रहे 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ओआईसी (आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन) की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया गया. पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था और भारत के आमंत्रण को रद्द करने की मांग कर रहा था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गया है तथा ओआईसी के संस्थापक देशों में से एक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है. पाकिस्तान की भारत को न्योता न देने मांग ही बेबुनियाद थी. उसका कहना था कि ओआईसी में केवल मुस्लिम देश शामिल हो सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और इस देश के मुस्लिम सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं. वैश्विक इस्लामिक समुदाय को भारत और वर्तमान सरकार पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने भारत को आमंत्रित किया. पिछले 70 सालों में पहली बार सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे पश्चिम एशियाई देशों को भारत पर भरोसा हुआ है और उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है. उनको भारत की कार्रवाइयों पर भरोसा है, जबकि आज तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता आया है और इस्लाम के नाम पर उनके बीच जगह बनाये रखता है. अब पाकिस्तान केवल धर्म का नाम लेकर नहीं बच सकता है.

हमारे कूटनीतिज्ञों और विदेश मंत्री ने केवल 2-3 दिनों के भीतर ही वैश्विक समर्थन जुटाया और पाकिस्तान पर अभिनंदन को छोड़ने का ऐसा दबाव कायम किया, जिससे पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना पड़ा. वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान ने अपनी छवि बना ली है कि वह दुनिया भर के देशों से मदद मांगता फिरता है, जबकि दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर करता है और आतंकियों को पनाह देता है. अमेरिका ने जो एफ-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दिया था, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, वह केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में या उनसे रक्षा में इस्तेमाल होना था. पाकिस्तान ने इस नियम का भी उल्लंघन किया है. भारत के पास यह सबूत हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए एफ-16 का इस्तेमाल किया है. इस उल्लंघन की वजह से अब भविष्य में पाकिस्तान इस तरह के लड़ाकू विमान या हथियार हासिल करने से भी वंचित रह जायेगा. ऐसे में कोई देश उसकी मदद नहीं करेगा. दस सालों से हम जिस कोशिश में थे, पुलवामा हमले के बाद अब ऐसा माहौल बन गया है कि चीन भी इस बार संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को बचाने नहीं आयेगा. खबर है कि अगले हफ्ते फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हो जायेगा और अपनी वीटो शक्ति से मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा देगा तथा चीन भी इसका विरोध नहीं करेगा. कुछ ही दिनों में भारत ने कूटनीति से अपने पक्ष में वैश्विक चेतना पैदा की है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था.

जारी हैं पाकिस्तान को अलग-थलग करने के कूटनीतिक प्रयास

भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित तीन आतंकी शिविरों पर हवाई हमले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान व सिंगापुर के विदेश मंत्रियों समेत पी5 देशों (सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देश) व अन्य देशों से बात कर अपना पक्ष रखा और उन्हें समझाया कि सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला करना भारत के लिए क्यों जरूरी हो गया था. आधिकारिक सूत्रों की मानें, तो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हवाई हमले को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है और ज्यादातर देशों ने यह माना है कि भारत की यह कार्रवाई असैनिक थी जो स्थान विशेष पर की गयी थी और उसका इरादा सैन्य बलों व नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं था. हमले के बाद भारत के साथ मजबूती से खड़े ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद, लश्करे तैयबा समेत आतंकी समूहों के खिलाफ त्वरित व अर्थपूर्ण कार्रवाई करने को कहा. इतना ही नहीं, 27 फरवरी को वुहान में हुए रूस-भारत-चीन (आरआईसी) समूह के त्रिपक्षीय सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्री वैंग यी से मुलाकात के दौरान भी सुषमा स्वराज ने पुलवामा आतंकी हमले और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया था. इससे पूर्व पुलवामा हमले के अगले ही दिन भारतीय विदेश सचिव नयी दिल्ली स्थित पी-5 देशों, सभी दक्षिण एशियाई देशों, जापान, जर्मनी, कोरिया सहित कई अन्य देशों के हेड ऑफ मिशन से भेंट की थी. वहीं, हमले के दो दिन बाद यानि 16 फरवरी को विदेश सचिव व अन्य सचिवों ने आसियान देशों, गल्फ को-ऑपरेशन कौंसिल, मध्य एशिया व अफ्रीकी देशों के राजदूतों से भेंट कर कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को अलग-थलग करने का प्रयास जारी रखा.

महत्वपूर्ण है ओआइसी में भारत का शामिल होना

पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उभरे तनाव के बीच एक मार्च को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ओआइसी (आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन) को संबोधित किया. ओआईसी के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के तौर पर आमंत्रित किया गया था. पांच दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस संगठन की बैठक में भारत को बुलाया गया है. मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत न तो ओआईसी का सदस्य है और न ही उसे इस संगठन ने पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया है. जबकि कम मुस्लिम आबादी वाले देश थाइलैंड और रूस को भी इस संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि शुरुआत से ही पाकिस्तान इस समूह में भारत के शामिल होने का विरोध करता रहा है. इस बार भी पाकिस्तान ने ओआईसी द्वारा भारत को दिये न्योते को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गयी. इससे नाराज पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार कर दिया. इस तरह से देखा जाये तो यह जहां भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, वहीं पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है. पाकिस्तान हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया है. इससे पहले 1969 में इस संगठन के पहले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत को न्योता दिया गया था, लेकिन तब पाकिस्तान की आपत्ति पर आखिरी वक्त में भारत को दिया न्योता रद्द कर दिया था और भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बीच रास्ते से लौटना पड़ा था. हालांकि भारत के ओआईसी के कई सदस्य देशों से अच्छे संबंध हैं. कतर ने तो वर्ष 2002 में पहली बार भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया था, वहीं तुर्की और बांग्लादेश भी भारत को इस संगठन का सदस्य बनाये जाने की मांग कर चुके हैं. इस बार न्योता देने वाले यूएई, जिसके साथ पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध काफी गहरे हुए हैं, की आबादी में एक तिहाई भारतीय हैं. ओआईसी से भारत को ऐसे समय न्योता आना, जब पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद वह पाकिस्तान को लेकर आक्रामक है और उसकी कूटनीतिक घेरेबंदी में लगा हुआ है, बेहद महत्व रखता है.

क्या है ओआईसी

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) मुस्लिम देशों का संगठन है. 25 सितंबर, 1969 को मोरक्को की राजधानी रबात में मुस्लिम देशों के हुए सम्मेलन में इसकी स्थापना का फैसला लिया गया था. इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर (आईसीएफएम) की 1970 में पहली मीटिंग हुई थी. वर्ष 1972 में ऑर्गनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस (वर्तमान में ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन) की स्थापना हुई. 57 सदस्यों वाले इस संगठन का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है. इसके मौजूदा महासचिव युसूफ बिन अहमद अल उसैमीन हैं.

वायुसेना के ये जांबाज भी रह चुके हैं पाकिस्तान की कैद में

- **एयर मार्शल केसी करियप्पा :** 1965 के युद्ध में केसी करियप्पा के विमान को पाक सेना ने मार गिराया था और वे पाकिस्तान में जा गिरे थे. चार महीने तक पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद वे वापस अपने देश आ गये थे.
- **फ्लाइट लेफ्टिनेंट जे एल भार्गव :** 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट जे एल भार्गव पाकिस्तानी सरजमीं पर उतर गये थे और वहां की सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे. एक साल तक वहां कैद में रहने के बाद वे वापस देश लौटे थे.
- **एयर वाइस मार्शल आदित्य विक्रम पेठिया :** 1971 युद्ध के दौरान एयर वाइस मार्शल आदित्य विक्रम पेठिया पांच महीने तक पाकिस्तान में युद्धबंदी बनकर रहे थे.
- **फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता :** 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता का विमान क्रैश होकर पीओके में जा गिरा था. आठ दिनों तक पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था.
- **विंग कमांडर दिलीप परुलकर, विंग कमांडर धीरेंद्र सिंह जाफा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम एस गरेवाल व हरिश सिंहजी, कर्नल अनिल ए अथले भी युद्धबंदी के तौर पर पाकिस्तान की जेल मे रह चुके हैं. हालांकि कई जांबाज ऐसे भी रहे जिन्हें कैद करने के बाद वहां मार दिया गया, वहीं कई ऐसे भी रहे जो वहां की जेल में ही मर गये. आज भी कई युद्धबंदी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.**

एफ-16 के इस्तेमाल पर मुसीबत में पाक

कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले के लिए एफ-16 विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन एजेंसी (डीएससीए) के अनुसार, पाकिस्तान को यह विमान आतंक के विरुद्ध अभियानों में अपनी क्षमता बढ़ाने और आतंकियों के खात्मे के लिए दिया गया था. इसके इस्तेमाल को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगभग 12 पाबंदियां लगायी हैं. हालांकि पाकिस्तान ने इस बात का खंडन किया है कि उसने भारत के खिलाफ एफ-16 का इस्तेमाल किया है. लेकिन भारतीय वायुसेना ने एफ-16 विमान के कुछ टुकड़े साक्ष्य के तौर पर पेश किये हैं, जिससे साबित होता है कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले के लिए पाकिस्तान ने इस विमान का इस्तेमाल किया था. असल में 26 फरवरी को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई हमला करने के अगले ही दिन एलओसी के नजदीक उड़ रहे 24 पाकिस्तानी विमानों को भारतीय लड़ाकू विमानों ने सीमा से दूर भगा दिया था. इन पाकिस्तानी विमानों में एफ-16 भी शामिल था. भारतीय सैनिकों द्वारा उड़ाये जा रहे 8 विमानों में मिग 21 बायसन विमान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे. अभिनंदन ने ही पाकिस्तान के एफ-16 विमान को हवा से हवा में मार करने वाली आर-73 मिसाइल दाग कर मार गिराया था. हालांकि, पाकिस्तान ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके किसी विमान को भारत ने मार गिराया है. वहीं, भारत के खिलाफ एफ-16 के इस्तेमाल को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा एफ-16 लड़ाकू विमान के गलत इस्तेमाल संबंधी रिपोर्टों पर अमेरिका और जानकारियां जुटा रहा है.

पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं था

डॉ भास्कर बालाकृष्णन
पूर्व एंबेसडर

विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान हर हाल में लौटाता, चाहे कुछ दिन बाद ही क्यों न लौटाता. पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प नहीं था. हालांकि, यहां कुछ बातें समझनेवाली हो सकती हैं. अभिनंदन को पाकिस्तान ने जितनी जल्दी रिहा किया है, इस संबंध में हम यह समझ सकते हैं कि यह भारत सरकार की कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है. लेकिन, इसके भी दो पहलू हैं. एक तरफ हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी कूटनीति दिखायी और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय संधि के अंतर्गत पाकिस्तान की मजबूरी भी थी. चाहे युद्धबंदी का मसला हो या फिर एक देश के किसी सैनिक का दूसरे देश में पकड़े जाने का मसला हो, इन सब पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही फैसले होते हैं. अब लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं कि कुलभूषण जाधव के मामले में यह सरकार तत्परता क्यों नहीं दिखाती. दरअसल, ये दोनों मामले अलग-अलग हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही स्तर पर नहीं देखा जा सकता है. अभिनंदन का मामला एक सैनिक का है, तो कुलभूषण का मामला जासूसी का है. जासूसी पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत फैसले नहीं हो सकते. दो देशों के बीच में या तो जब युद्ध होता है तब, या फिर युद्ध की घोषणा भी न हुई हो उस सूरत में भी अगर सैन्य झड़प होती है तब, इन दोनों परिस्थितियों में जब कोई सैनिक लड़ते-लड़ते दूसरे देश की सीमा में पकड़ लिया जाता है, तब जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही उसे रिहा किया जाता है. अभिनंदन के मामले में यही हुआ है. यह एक अंतरराष्ट्रीय मामला है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर ही निर्णय लिया जाना था और लिया भी गया.